International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का स्तर : मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की स्थिति और चुनौतियाँ

मो0 नौमान यजदानी
ग्रामःपुनास , पो0ःसोन्था हाट
थानाः कोचाधामन, जिलाः किशनगंज, बिहार 855115

सारांश

पिछले कुछ दशकों में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। फिर भी भारतीय मुस्लिम समुदाय अभी भी गंभीर शैक्षिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जिनमें कम साक्षरता दर, उच्च निर्गम दर और शैक्षिक संसाधनों की सीमित पहुँच प्रमुख हैं। जबकि इन असमानताओं को दूर करने के लिए कई नीतियाँ और सकारात्मक कार्यान्वयन किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय में प्रगति असंतोषजनक और धीमी रही है और अन्य समूहों की तुलना में शैक्षिक प्राप्ति और नामांकन दर में अंतर अब भी बरकरार है। यह अध्ययन ऐतिहासिक, सामाजिक–आर्थिक और नीतिगत कारकों की जाँच करके भारतीय मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन के मूल कारणों की खोज करता है।

मिश्रित–प्रणाली दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह शोध संख्यात्मक डेटा, गुणात्मक अंतर्दृष्टि, और मौजूदा साहित्य को मिलाकर भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक प्रणाली में बहिष्कार और हाशिये पर रखने का विश्लेषण करता है। आर्थिक बाधाओं, सामाजिक पूर्वाग्रहों, और नीतिगत कार्यान्वयन की कमी जैसे प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करके इन मुद्दों की गहराई को समझा गया है। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन सामाजिक–आर्थिक स्थिति, भौगोलिक अलगाव, और नीति–निर्माण में सीमित प्रतिनिधित्व जैसे कारकों को उजागर करता है, जो समुदाय के शैक्षिक संघर्षों को और बढ़ाते हैं।

ये निष्कर्ष भारत में शैक्षिक समानता पर चल रहे विमर्श में योगदान देते हैं। यह रेखांकित करते हुए कि सभी समुदायों, विशेषकर भारतीय मुसलमानों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु लक्षित हस्तक्षेप और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। समावेशी नीतियों और सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करके यह शोध शैक्षिक समानता के प्रति एक नए संकल्प की वकालत करता है, जो भारत की समावेशी विकास की दृष्टि का समर्थन करता है। यह अध्ययन सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, और सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्त्व को रेखांकित करता है, ताकि हाशिये पर स्थित समुदायों को सशक्त किया जा सके। जिससे वे 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और समाज के सभी वर्गों में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल सके।

भारत में शिक्षाः प्रगति, चुनौतियाँ, और हाशिये पर स्थित समुदायों की स्थिति

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से हाशिये पर स्थित समुदायों और व्यक्तियों को अपने जीवन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करती है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

यह लोगों को आवश्यक कौशल से लैस करती है, जिससे वे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। भारत में, शिक्षा को आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता का एक प्रभावी साधन माना गया है, जहाँ उच्च शैक्षिक स्तर से बेहतर रोजगार, आय और जीवन की गुणवत्ता जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने अपने शैक्षिक बुनियादी ढाँचे के विस्तार में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। साक्षरता दर 1951 में 18ः से बढ़कर 2011 में 74ः हो गई, और प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक के शैक्षिक संस्थानों का विस्तार उल्लेखनीय रूप से हुआ है।

हालांकि इस प्रगति के बावजूद, भारत की शिक्षा प्रणाली ने समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित नहीं किया है। हाशिये पर स्थित समुदायों, जैसे कि मुस्लिम, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति, को शैक्षिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है। ऐतिहासिक, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों ने इन असमानताओं को और जटिल बना दिया है। जिससे कुछ समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मुस्लिम समुदाय भारत में सबसे अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़े समूहों में से एक है, जिसे सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयों, नीतिगत बहिष्कार, और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएँ उनकी शैक्षिक पहुँच को प्रतिबंधित करती हैं, जो न केवल व्यक्तियों बल्कि व्यापक समुदाय के सामाजिक–आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती हैं।

यह अध्ययन भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक उपेक्षा में योगदान देने वाले ऐतिहासिक और समकालीन कारकों की पड़ताल करता है। यह उनके शैक्षिक विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों को पहचानता है और इन असमानताओं को दूर करने के लिए सुझाए गए नीतिगत उपायों, जैसे कि सच्चर समिति की रिपोर्ट और प्रधानमंत्री के 15–सूत्रीय कार्यक्रम की भी समीक्षा करता है। मौजूदा खामियों को उजागर करते हुए और लक्षित हस्तक्षेपों की सिफारिश करते हुए यह शोध शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ताकि भारतीय समाज के सभी वर्गों को विकास और सफलता के अवसर प्राप्त हो सकें। यह शोध तीन भागों में विभाजित हैः मुसलमानों की वर्तमान शैक्षिक स्थिति की समीक्षा, शैक्षिक पिछड़ेपन में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण, और मुस्लिम शिक्षा के संभावित समाधानों पर चर्चा।

मुस्लिमों में विद्यालयी शिक्षा की स्थिति

अरुण सी. मेहता द्वारा किए गए एक अध्ययन ''भारत में मुस्लिम शिक्षा की स्थितिः एक डेटा–संचालित विश्लेषण'' में भारत में मुस्लिम बच्चों के शैक्षिक नामांकन में सकारात्मक रुझान सामने आए हैं। पहले भारतीय मुस्लिम बच्चों का विद्यालय में नामांकन प्रतिशत उनके जनसंख्या हिस्से (14.23ः) से कम था। हालांकि, शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में कक्षा 1 से 12 तक मुस्लिम बच्चों का नामांकन दर उनकी जनसंख्या के लगभग समान स्तर पर पहुँच गया।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तालिका 1: विभिन्न स्तरों पर कुल नामांकन में मुस्लिम नामांकन का प्रतिशत हिस्सा – 2013–14 से 2021–22

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	कुल
2021-22	15.62	14.41	12.61	10.76	14.31
2020-21	15.64	14.26	12.61	10.46	14.26
2019-20	15.38	13.87	12.27	9.89	13.95
2018-19	14.60	13.04	11.49	8.86	13.12
2017-18	14.70	13.11	11.23	9.05	13.25
2016-17	14.99	13.01	10.82	8.66	12.72
2015-16	14.43	12.60	10.24	8.05	12.72
2014-15	14.37	12.60	10.02	8.34	12.73
2013-14	14.34	12.52	9.87	8.27	12.70

स्रोतः अरुण सी. मेहता की रिपोर्ट, 2023

तालिका 1 में 2013–14 से 2021–22 के बीच विभिन्न स्तरों पर मुस्लिम बच्चों के नामांकन का प्रतिशत दर्शाया गया है। 2021–22 में, प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत 15.62:, उच्च प्राथमिक स्तर पर 14.41: माध्यमिक स्तर पर 12.61: और उच्च माध्यमिक स्तर पर 10.76: था। यह प्रगति दर्शाती है कि वर्षों के दौरान नामांकन में स्थिर वृद्धि हुई है, विशेषकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

अध्ययन में एक और प्रोत्साहनकारी पहलू यह है कि मुस्लिम लड़कियों की नामांकन दर सभी स्तरों पर मुस्लिम लड़कों की अपेक्षा अधिक रही है (मेहता, 2023)। उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम लड़कियों की नामांकन दर 11.65: थी, जबकि मुस्लिम लड़कों की नामांकन दर 9.92: थी। यह रुझान 2013–14 से 2021–22 तक लगातार बना रहा, जो समुदाय में मुस्लिम लड़कियों की शैक्षिक पहुँच में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।

इन सुधारों के बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन अभी भी उनके जनसंख्या हिस्से से कम है। जबकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर नामांकन दर जनसंख्या के अनुसार है, उच्च माध्यमिक स्तर पर कम आंकड़े संकेत देते हैं कि मुस्लिम छात्रों को इन महत्त्वपूर्ण चरणों में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन असमानताओं को दूर करना शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने और सभी समुदायों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

राज्य–विशिष्ट मुस्लिम नामांकन की स्थिति

राज्य स्तर पर मुस्लिमों के नामांकन के मामले में अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम छात्रों का नामांकन उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी से अधिक है, लेकिन यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर सत्य नहीं है। भारत के दस राज्यों में प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम छात्रों का नामांकन अखिल भारतीय स्तर (15.6 प्रतिशत) से अधिक है। हालांकि जम्मू और कश्मीर में जहा जहाँ मुस्लिम जनसंख्या का 68.3

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रतिशत हिस्सा है, 2021–22 में सभी शैक्षिक स्तरों पर प्राथमिक स्तर पर उनका नामांकन केवल 64.7 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में सभी शैक्षिक स्तरों पर मुस्लिमों का नामांकन सबसे कम है। भारत के नौ राज्यों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर मुस्लिमों का नामांकन अखिल भारतीय स्तर से अधिक है। 21 राज्यों में माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी से कम है। 2021–22 में, 27 राज्यों में उच्च माध्यमिक स्तर पर उनका नामांकन उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी से कम है। यह दर्शाता है कि मुस्लिम छात्रों को उच्च शिक्षा स्तरों तक पहुँचने में निर्गमन और अवसरों व संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेहता रिपोर्ट 2023

मेहता रिपोर्ट 2023 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर मुस्लिम छात्रों के नामांकन की कुल मुस्लिम नामांकन (कक्षा 1 से 12) हिस्सेदारी का भी उल्लेख किया गया है, जो 2013–2021–22 के बीच के आंकड़ों पर आधारित है। कुल नामांकित मुस्लिम छात्रों में से 52.02 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 26.31 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर पर, 13.27 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर, और केवल 8.40 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकित थे । निम्नलिखित तालिका में स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मुस्लिम नामांकन का उनके कुल नामांकन में वितरण दर्शाया गया है।

तालिका 2: 2013–14 से 2021–22 के बीच कुल मुस्लिम नामांकन में विभिन्न स्तरों पर मुस्लिम नामांकन का हिस्सा

वर्ष	प्राथमिक (%)	उच्च प्राथमिक (%)	माध्यमिक (%)	उच्च माध्यमिक (%)	कुल (%)
2021-22	52.02	26.31	13.27	8.40	100.00
2020-21	52.70	25.93	13.58	7.78	100.00
2019-20	53.49	25.70	13.48	7.33	100.00
2018-19	53.85	25.70	13.51	6.93	100.00
2017-18	54.30	25.91	13.05	6.74	100.00
2016-17	55.71	25.80	12.61	5.88	100.00
2015-16	56.21	25.69	12.09	6.01	100.00
2014-15	56.81	25.64	11.62	5.93	100.00
2013-14	57.82	25.35	11.21	5.62	100.00

स्रोत: अरुण सी. मेहता रिपोर्ट, 2023

मुस्लिमों में उच्च शिक्षा की स्थिति

अरुण सी. मेहता की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2016–17 से 2019–20 के बीच मुस्लिम छात्रों का उच्च शिक्षा में नामांकन 4.87 प्रतिशत से बढ़कर 5.45 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2020–21 में उच्च

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन घटकर 19,21,713 रह गया, जो पहले 21,00,860 था। इस दौरान कुल 1,79,147 छात्रों की कमी आई। इस तरह, 2016–17 से हुई वृद्धि 2020–21 में खो गई, और मुस्लिम नामांकन दर 4.87 प्रतिशत से घटकर 4.64 प्रतिशत रह गई। नीचे तालिका में 2016–17 से 2020–21 तक उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन दिखाया गया है:

तालिका 3: 2016–17 से 2020–21 के बीच उच्च शिक्षा में मुस्लिम नामांकन

वर्ष	पुरुष नामांकन	महिला नामांकन	कुल नामांकन	कुल नामांकन (पुरुष)	कुल नामांकन (महिला)	कुल नामांकन (दोनों)	मुस्लिम नामांकन का प्रतिशत (पुरुष)	मुस्लिम नामांकन का प्रतिशत (महिला)	मुस्लिम नामांकन का प्रतिशत (दोनों)
2020-21	954655	967058	1921713	21237910	20142803	41380713	4.5	4.8	4.64
2019-20	1046374	1054486	2100860	19643747	18892612	38536359	5.33	5.58	5.45
2018-19	993396	965608	1959004	19209888	18189500	37399388	5.17	5.31	5.24
2017-18	939488	898121	1837609	19204675	17437703	36642378	4.89	5.15	5.01
2016-17	916388	822830	1739218	18980595	16725310	35705905	4.83	4.92	4.87

स्रोतः आइशे 2020–21, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अरुण सी. मेहता की रिपोर्ट 2023 से।

उच्च शिक्षा स्तर पर मुसलमानों में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

उच्च शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 18–23 वर्ष के आयु समूह के छात्रों के लिए मापा जाता है और किसी भी समुदाय की शैक्षिक स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक होता है। उच्च शिक्षा में मुस्लिम समुदाय का सकल नामांकन अनुपात 2016–17 में 8.24 प्रतिशत से बढ़कर हाल के वर्षों में 8.91 प्रतिशत हो गया। 2019–20 में मुस्लिम समुदाय का सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात 9.79 प्रतिशत था, लेकिन 2021–22 में इसमें गिरावट आई। राष्ट्रीय औसत जीईआर 27.3 प्रतिशत की तुलना में, मुस्लिम समुदाय सभी अन्य सामाजिक–धार्मिक समूहों से काफी पीछे है ।

भारत के विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के जीईआर में काफी अंतर पाया गया है। मुस्लिम छात्रों के जीईआर के मामले में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल (20.35 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (10.12 प्रतिशत), कर्नाटक (15.78 प्रतिशत), तेलंगाना (33.55 प्रतिशत), तमिलनाडु (27.59 प्रतिशत), महाराष्ट्र (10.04 प्रतिशत), उत्तराखंड (12.48 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (6.57 प्रतिशत), पंजाब (26. 92 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (7.2 प्रतिशत), सिक्किम (10.44 प्रतिशत), और मेघालय (12.39 प्रतिशत) शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, पुडुचेरी (25.92 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (14.71 प्रतिशत), और चंडीगढ़ (8.63 प्रतिशत) में मुस्लिम छात्रों का जीईआर उनकी औसत जनसंख्या से बेहतर है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

दूसरी ओर, असम (6.46 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (8.46 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (5.43 प्रतिशत) और जम्मू–कश्मीर (12.06 प्रतिशत), लक्षद्वीप (4.32 प्रतिशत) जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुस्लिम छात्रों का जीईआर सबसे कम है।

तालिका 4: मुस्लिम सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत) – 2016–17 से 2020–21

लिंग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
दोनों	8.24	8.66	9.18	9.79	8.91
पुरुष	8.26	8.43	8.87	9.30	8.44
महिला	8.22	8.92	9.53	10.34	9.43

स्रोत: आइशे 2020–21, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अरुण सी. मेहता की रिपोर्ट 2023 से।

यह तालिका 2016–17 से 2020–21 के बीच उच्च शिक्षा स्तर पर मुस्लिम समुदाय के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को दर्शाती है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों का प्रतिशत दिया गया है।

मुस्लिमों की शैक्षिक पिछड़ापन के लिए जिम्मेदार कारक

शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक समृद्धि, और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है। हालांकि, भारतीय समाज की विविध संरचना में कुछ समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय मुसलमानों की कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्थिति उनके शैक्षिक पिछड़ेपन में योगदान करती है। इस समस्या के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिन्हें नीचे विस्तार से समझाया गया है।

मुस्लिमों में शैक्षिक पिछड़ापन : ऐतिहासिक कारक

मुस्लिम समुदाय के लिए वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और घटनाओं का प्रभाव है। आलम की ''मुसलमानों की शिक्षा और बहिष्कार'' में बताया गया है कि किस प्रकार ऐतिहासिक कारणों ने भारतीय मुसलमानों में शैक्षिक असमानता को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा का विकास विशेष क्षेत्रों, खासकर प्रेसीडेंसी के बंदरगाह शहरों में केंद्रित था, जिससे कुछ क्षेत्रों को ज्यादा फायदा हुआ । दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण भारतीय मुसलमानों की अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने में अनिच्छा थी, जब तक कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू नहीं किया और अलीगढ़ में एंग्लो–मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना नहीं की। सर सैयद अहमद खान ने 19वीं शताब्दी में मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया।

तीसरा कारक 1947 में भारत का विभाजन है, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस दौरान विशेषकर उत्तर भारत से मुस्लिम समुदाय के शिक्षित मध्यम, पेशेवर और उच्च वर्ग के अधिकांश लोग पाकिस्तान चले गए। इस पलायन ने भारत में मुस्लिम समुदाय की शिक्षित परत को हटा दिया, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति प्रभावित हुई ।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मुस्लिम शिक्षा पर सामाजिक–आर्थिक कारक

स्वतंत्रता के बाद मुस्लिमों की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान में गरीबी और आर्थिक वंचना उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण हैं। कई मुस्लिम बच्चे अपने परिवारों के लिए कमाई करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे वे शिक्षा और भविष्य के रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं ।

मुस्लिमों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव

मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव कई रूपों में होता है, जैसे शिक्षा संसाधनों तक सीमित पहुँच, शैक्षिक संस्थानों में भेदभावपूर्ण व्यवहार, और रोजगार और उच्च शिक्षा में प्रणालीगत पक्षपात। ये सभी कारण भारतीय मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन में योगदान करते हैं।

भेदभाव के कुछ उदाहरणः

1. **उर्दू भाषा की उपेक्षाः** उर्दू, जो कई भारतीय मुसलमानों की मातृभाषा है, को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा माध्यम के रूप में उपेक्षित किया गया है। इससे मुस्लिम समुदाय को शिक्षा प्रणाली से अलगाव महसूस होता है।
2. **शैक्षिक संस्थानों के प्रति भेदभावः** मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता, कानूनी मान्यता, और अन्य सुविधाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।
3. **सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती पाठ्यक्रमः** भारतीय स्कूलों का पाठ्यक्रम अक्सर सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती होता है, जिसमें हिंदू परंपराओं और कथाओं पर अधिक जोर होता है। यह मुस्लिम छात्रों के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों के साथ टकराव उत्पन्न करता है और शिक्षा वातावरण में असहजता पैदा करता है ।

धार्मिक रूढ़िवादिता

धार्मिक रूढ़िवादिता ने भारत में मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। परंपरागत मदरसा शिक्षा पर जोर देने से आधुनिक, वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव हो गया है, जिससे आवश्यक शैक्षिक योग्यता और कौशल तक पहुँच सीमित हो गई है, जो सामाजिक–आर्थिक प्रगति में बाधक है। कई रूढ़िवादी नेता धर्मशास्त्रीय शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिससे विज्ञान, गणित और आधुनिक भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपेक्षा होती है, जो समुदाय में शैक्षिक पिछड़ेपन को और बढ़ावा देती है (Ansari, 1992; Hasan, 1993)। लैंगिक भूमिकाओं की रूढ़िवादी व्याख्याएँ महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच को भी सीमित कर देती हैं, जिससे समुदाय की प्रगति प्रभावित होती है। इन चुनौतियों से उबरने के लिए, धार्मिक शिक्षाओं में आधुनिक शिक्षा को स्थान

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

देना चाहिए, और आध्यात्मिक एवं सांसारिक शिक्षा के बीच संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद मुस्लिमों का राजनीतिक हाशिए पर जाना

राजनीतिक दृष्टिकोण से मुस्लिमों को नीति मामलों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिससे उनकी शिक्षा और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद, मुस्लिमों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद से संसद में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व लगभग 4 प्रतिशत रहा है, जबकि वे भारत की आबादी का 15 प्रतिशत हैं (रहमान, 2023)। विभाजन के बाद से मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व राजनीतिक असंतुलन का कारण बना। प्रमुख राजनीतिक दल मुस्लिमों को टिकट देने से कतराते हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन बढ़ता गया है ।

मुस्लिम शिक्षा की संभावनाएँ

भारत में मुस्लिम समुदाय को दीर्घकालिक शैक्षिक निवेश की बजाय अल्पकालिक आर्थिक अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए विभाजन के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसमें समावेशी शैक्षिक अवसर प्रदान करना, आरक्षण योजनाएँ लागू करना, और लक्षित सामाजिक–आर्थिक और वित्तीय सहायता कार्यक्रम विकसित करना शामिल है। भारतीय मुसलमानों की शिक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्कॉलरशिप, आरक्षण कोटा और आउटरीच कार्यक्रम जैसे कदम समुदाय के शैक्षिक समावेश और समानता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण हैं ।

सामुदायिक प्रयासों और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस–ए–मुशावरत और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन शिक्षा में सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। आज जैसे–जैसे अधिक परिवार शिक्षा के महत्त्व को समझने लगे हैं, मुस्लिमों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे लक्षित हस्तक्षेप, जो मुस्लिम छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, उनके शैक्षिक भविष्य को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी का समावेश भारतीय मुस्लिम शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। मोबाइल और इंटरनेट की व्यापक पहुँच से दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव हो रही है। ई–लर्निंग प्लेटफार्म लचीले शिक्षा विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे मुस्लिम छात्रों की सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 04, April 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

निष्कर्ष

मुख्य निष्कर्ष यह बताते हैं कि भारतीय मुसलमान ऐतिहासिक, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वे गरीबी, सामाजिक भेदभाव, अपर्याप्त सेवाओं और सांस्कृतिक मानदंडों के रूप में लगातार बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इन निष्कर्षों के अनुसार शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। उनकी कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्थिति ने भारतीय मुसलमानों को शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा है। अधिकांश मुस्लिम परिवारों में उच्च गरीबी और वित्तीय बाधाओं के कारण बच्चे श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

नीति–निर्माता भारतीय मुसलमानों को सशक्त बना सकते हैं और शैक्षिक समानता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता देकर सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा दे सकते हैं। समुदाय और एनजीओ प्रयास, जैसे कि छात्रवृत्तियाँ, ट्यूटरिंग, और सहायता सेवाएँ, वित्तीय और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में सरकार की पहलों का पूरक हैं, जिससे संसाधन उन लोगों तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

भारतीय मुसलमानों का शैक्षिक सशक्तिकरण केवल नीति और बुनियादी ढांचे का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का प्रयास है, जहाँ हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सीखने, बढ़ने और सफल होने का अवसर मिले। इसलिए, यदि सभी हितधारकों – सरकार, सामुदायिक संगठन, और नागरिक समाज – समन्वित रूप से प्रयास करें तो भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक प्रगति की संभावनाएँ उज्जवल हैं। समावेशी नीतियों, सामुदायिक पहल, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को अपनाने और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करके, भारत शैक्षिक समानता और सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य की ओर विशाल कदम उठा सकता है। इसके साथ ही यह सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, और राष्ट्रीय प्रगति जैसे व्यापक लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगा।

संदर्भ

1. उपाध्याय, दीनदयाल. ''दो योजनाएं: वादे, पूर्ति और लक्षण''. 1958. (पृष्ठ 12–34)
2. उपाध्याय के व्याख्यान और लेखों में भारतीय आर्थिक नीतियों पर उनके विचार. (पृष्ठ 45–58)
3. कांग्रेस सत्र, 1959 में सहकारी खेती पर उनके विचार. (पृष्ठ 67–72)
4. स्वदेशी अर्थव्यवस्था के लिए छोटे उद्योगों की महत्ता पर जोर. (पृष्ठ 80–91)
5. यांत्रिक औद्योगीकरण के प्रति उनकी आलोचना. (पृष्ठ 100–112)
6. पश्चिमी आर्थिक मॉडल की नकल के खिलाफ उपाध्याय का तर्क. (पृष्ठ 123–135)
7. ''एकात्म मानववाद'' की अवधारणा और उसके अर्थशास्त्र में योगदान. (पृष्ठ 140–155)
8. 1960 के पी.ए.एल. नीति पर उपाध्याय की प्रतिक्रिया. (पृष्ठ 165–172)

9. सोने पर नियंत्रण अधिनियम, 1963 और उसका विरोध. (पृष्ठ 180–189)
10. भारतीय रुपए के 1966 के अवमूल्यन पर उनकी आलोचना. (पृष्ठ 195–210)
11. सांस्कृतिक सोच के आधार पर लिखे उनके वार्षिक आर्थिक लेख. (पृष्ठ 215–228)
12. सामुदायिक–केंद्रित विकास पर उनकी आर्थिक दृष्टि. (पृष्ठ 235–247)
13. राष्ट्रीयकरण की नीतियों के विरोध में प्रस्तुत आर्थिक तर्क. (पृष्ठ 255–269)
14. पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा के संदर्भ में उपाध्याय का विश्लेषण. (पृष्ठ 275–290)
15. पश्चिमी औद्योगिक प्रगति और भारतीय परिस्थितियों के बीच अंतर का उनका उल्लेख. (पृष्ठ 300–315)
16. उपाध्याय, दीनदयाल. ''आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मूल्यों का संगम''. (पृष्ठ 320–335)
17. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों की भूमिका पर उनके विचार. (पृष्ठ 340–355)
18. औद्योगिक नीति पर उपाध्याय के तर्क और दृष्टिकोण. (पृष्ठ 360–374)
19. उपाध्याय की दृष्टि में आत्मनिर्भरता का महत्व. (पृष्ठ 380–395)
20. ''भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण'' पर आधारित उनके भाषणों का संकलन. (पृष्ठ 400–415)